(M.M. कुमार, जे।)

एमएम कुमार, जे. के समक्ष

शमशेर – याचिकाकर्ता

बनाम

अनुराग अग्रवाल और दूसरा – *उत्तरदाताओं*

सी .ओ . सी.पी. 2003 की संख्या 1478 सी .डब्लू .पी . 2003 की संख्या 11144

19 सितंबर, 2005

न्यायालय की अवमान अधिनियम, 1971 – धारा 10 और 12 –बी.डी.-पी.ओ. द्वारा संचालित प्रारंभिक जांच में एक सरपंच के ख़िलाफ़ हेराफेरी का आरोप साबित हुई - डी.सी. ने उसे निलंबन किया और उसके खिलाफ नियमित जांच का आदेश दिया –डी.सी. के आदेश के विरुद्ध अपील को आयुक्त-सह-सचिव ने खरीच किया - उच्च न्यायालय में सरपंच द्वारा याचिका वापस ले लिया मानकर खरीच कर दिया गया - याचिकर्ता ने उच्च न्यायालय में याचिका डायर कर उत्तरदाताओ को उसे और अन्य गवाहों को उचित अवसर देकर निष्पक्ष जाँच करने का निर्देश देके की माँग कि - याचिका खरीच की राज्य के वकील की is दलील पर की जाँच बिना किसी हस्तशेप से प्रभावित हुए ओए रिकॉर्ड पर लायी गई सामग्री के आधार पर शीघ्रता से पूरी की जाएगी - सरपंच के खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है और बहाली का आदेश पारित हो चुका है-राज्य वकील द्वारा दिया गया बयान सत्य माना जाना चाहिए - *न्याय प्रशासन में बाधा* - न्यायालय को दिए गए वचन का घोर उल्लंघन किया गया है और यह अधिनियम की धारा 2(बी) के अर्थ के अंतर्गत नागरिक अवमानना है - *दोनों उत्तरदाताओं को अधिनियम की धारा 2(बी) के तहत परिकल्पित नागरिक अवमानना का दोषी माना गया ।*

अभिनिर्णित, यह न्याय प्रशासन में बाधा डालने का एक शास्त्रीय उदाहरण है। संशोधित रिट याचिका 4 अगस्त, 2003 को दायर की गई, जो 5 अगस्त, 2003 को विचार के लिए आई।मामले की तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए, खंडपीठ ने महाधिवक्ता को नोटिस जारी किया था। जब मामला उठाया गया, तो यह बयान देकर याचिका खारिज कर दी गई कि याचिकाकर्ता को जांच में पूरा मौका दिया जाना था और उसकी दुर्भावनापूर्ण और पक्षपातपूर्ण सभी आशंकाएं निराधार थीं। तदनुसार, याचिकाकर्ता को प्रारंभिक जांच के दौरान दर्ज किए गए निष्कर्षों के संबंध में जो भी साक्ष्य उचित लगे, जो स्पष्ट रूप से सरपंच के खिलाफ थे, पेश करने की छूट देते हुए रिट याचिका का निपटारा कर दिया गया। हालाँकि, यह माना गया है कि खंडपीठ द्वारा 5 अगस्त, 2003 के आदेश में दर्ज बयान देने से पहले, सरपंच की बहाली का आदेश पहले ही पारित किया जा चुका था और उसने रुपये रु.98,395 दंडात्मक ब्याज सहित, की राशि 4 अगस्त, 2003 को जमा कर दी थी।आगे यह माना गया है कि जांच 25 जुलाई, 2003 को पूरी हो गई थी। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि 25 जुलाई, 2003 को जांच पूरी होने और 4 अगस्त, 2003 को सरपंच की बहाली के आदेश पारित होने के बावजूद, प्रतिवादी संख्या 1 और 2 5 अगस्त, 2003 को वरिष्ठ उप महाधिवक्ता

के माध्यम से न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए और एक बयान दिया, जो रिकॉर्ड से बाहर नहीं है।इस तथ्य के अलावा कि 5 अगस्त, 2003 को न्यायालय को दिए गए वचन का घोर उल्लंघन किया गया है और यह अधिनियम की धारा 2 (बी) के अर्थ के तहत नागरिक अवमानना का गठन करता है, प्रतिवादियों द्वारा दिया गया गलत बयान न्याय प्रशासन में बाधा डालने की सीमा पर है।

(पैरा 16)

आगे आयोजित किया गया,उत्तरदाताओं का यह रुख कि कोई बयान नहीं दिया गया था, इस कारण से स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि अदालतें महाधिवक्ता या अदालत में किसी अन्य राज्य के वकील द्वारा दिए गए बयान के पीछे नहीं जा सकती हैं।उन कथनों को तथ्य के आधार पर सही मानना होगा क्योंकि यदि उन कथनों पर संदेह किया गया तो न्याय की मशीनरी चरमरा जाएगी और विफल हो जाएगी। इसलिए, मुझे उत्तरदाताओं द्वारा अपनाए गए रुख में कोई सार नहीं दिखता।

(पैरा 19)

आगे आयोजित किया गया, कि प्रतिवादियों द्वारा सरपंच के खिलाफ निष्पक्ष जांच कराने का आश्वासन देने वाले बयान पर रिट याचिका खारिज कर दी गई और रिट याचिका का निपटारा कर दिया गया। 5 अगस्त, 2005 के आदेश में, मैंने स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया है कि उत्तरदाता अवमानना के दोषी थे और उनका आचरण अवमाननापूर्ण था। प्रतिवादियों द्वारा अवमानना को दूर करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। इसके विपरीत, दोनों प्रतिवादियों द्वारा एक रहस्यमय और अज्ञात अधिकारी पर जिम्मेदारी डालने की अपनी कार्रवाई को यह कहकर उचित ठहराने का प्रयास किया गया है कि उसने इस न्यायालय को गलत निर्देश दिए होंगे, जिसके कारण याचिका का निपटान हुआ। ऐसा रहस्यमय व्यक्ति अस्तित्व में नहीं है। इसलिए, मैं दोनों उत्तरदाताओं को अधिनियम की धारा 2(बी) के अनुसार नागरिक अवमानना का दोषी घोषित करता हूं।

(पैरा 21)

मदन पाल, एडवोकेट, *याचिकाकर्ता के लिए*

हवा सिंह हुडा, एडवोकेट जनरल, कमल शर्मा के साथ हरियाणा, अतिरिक्त एडवोकेट जनरल, हरियाणा, *के लिए उत्तरदाताओं.*

आदेश

एम.एम. कुमार जे.

(1) न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 (अधिनियम की संक्षिप्तता के लिए) की धारा 10 और 12 के तहत दायर यह याचिका, न्याय प्रशासन में बाधा डालने और बाधित करने का एक शास्त्रीय उदाहरण है। याचिकाकर्ता द्वारा की गई शिकायत यह है कि राज्य के वकील के माध्यम से उत्तरदाताओं द्वारा दिए गए बयान पर आधारित 5 अगस्त, 2003 का वचनपत्र झूठा था।यह उल्लेख करना उचित होगा कि बयान के आधार पर याचिकाकर्ता द्वारा दायर सिविल रिट याचिका संख्या 11144/2003 का निपटारा कर दिया

गया और डिवीजन बेंच ने उत्तरदाताओं को निर्देश जारी किए हैं। परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता को अपूरणीय क्षति हुई है और उत्तरदाताओं को कानून के अनुसार दंडित करने की प्रार्थना की गई है।

(2) संक्षेप में तथ्य यह है कि श्रीमती. चन्नो देवी ग्राम पंचायत, फिरोजपुर, जिला कैथल की सरपंच के रूप में कार्यरत थीं। उनके खिलाफ अन्य बातों के साथ-साथ हेराफेरी के भी गंभीर आरोप थे। प्रतिवादी नंबर 2 श्री चंद राम, तत्कालीन खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, गुहला ने सरपंच द्वारा कराए गए विकास कार्यों की मूल्यांकन रिपोर्ट बनाई थी। प्रारंभिक जांच की गई और प्रथम दृष्टया उसके खिलाफ आरोप साबित हुए। 19 दिसंबर, 2002 को प्रतिवादी नंबर 1, जो उस समय कैथल के उपायुक्त थे, ने एक आदेश पारित कर सरपंच को निलंबित कर दिया। तदनुसार, सरपंच पर आरोप पत्र दायर करते हुए उसके खिलाफ नियमित जांच का आदेश दिया गया। प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा पारित आदेश दिनांक 19 दिसंबर, 2002 इस प्रकार है: -

> *"खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी गुहला की रिपोर्ट के अनुसार वि.सं. 588, 589 दिनांक 15 अप्रैल 2002 एवं कार्यपालन यंत्री द्वारा किये गये विकास कार्यों की मूल्यांकन रिपोर्ट क्रमांक 897 दिनांक 7 नवम्बर 2002, श्रीमती चन्नो देवी, सरपंच ग्राम पंचायत, फिरोजपुत ब्लॉक गुहला को गंभीर आरोपों का दोषी पाया गया है, इसलिए इस कार्यालय के पत्र संख्या 1828, दिनांक 6 मई, 2002 और 5236, दिनांक 4 दिसंबर, 2002 के माध्यम से जवाब देने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। श्रीमती चन्नो देवी ने 4 जून, 2002 और 11 दिसंबर, 2002 को अपना जवाब प्रस्तुत किया, जिसे देखने पर संतोषजनक नहीं पाया गया। इसके बाद सरपंच को 18 जुलाई, 2002 और 12 दिसंबर, 2002 को अपने साक्ष्य के साथ उपस्थित होने के लिए व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया। सरपंच ने उपस्थित होकर अनुरोध किया कि उनके द्वारा प्रस्तुत उत्तर को उनका साक्ष्य माना जाए। सरपंच ने अपने जवाब में कहा है कि उनके द्वारा किए गए सभी कार्य पंचायत द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव के बाद और माप पुस्तिका के अनुसार किए गए थे, लेकिन कार्यकारी अभियंता द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार, सरपंच ने कार्यों पर अधिक राशि खर्च की है। और वर्ष 2001-2002 के रिकॉर्ड के अनुसार, उसने शामलात भूमि की लीज राशि से सीधे 2,17,000 रुपये की राशि खर्च करके अवैध तरीके से पंचायत निधि का दुरुपयोग किया है। आरोपों की गंभीरता को देखते हुए पत्रांक 5496-5500, दिनांक 19 दिसंबर 2002 के तहत उसके खिलाफ आरोप पत्र दायर कर नियमित जांच का आदेश दिया गया है। अत: इन परिस्थितियों में सरपंच का सरपंच पद पर बने रहना जनहित में नहीं है। इसलिए, मैं अनुराग अग्रवाल, आईएएस, उपायुक्त, कैथल, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 51(1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्रीमती छन्नो देवी, सरपंच, ग्राम पंचायत, फिरोजपुर, ब्लॉक गुहला को मामले के लंबित रहने के दौरान निलंबित करता हूं। पूछताछ की और आदेश*

दिया कि वह भविष्य में पंचायत की कार्यवाही की किसी भी बैठक में भाग नहीं लेंगी और पंचायत की चल/अचल संपत्ति का प्रभार बहुमत प्राप्त पैनल को सौंप देंगी। यह आदेश तुरंत लागू किया जाएगा।

उपायुक्त, कैथल"

(प्रतिवादी संख्या I)

(3) उपरोक्त आदेश के खिलाफ, सरपंच ने वित्तीय आयुक्त और सचिव, हरियाणा सरकार, पंचायत विभाग, चंडीगढ़ के समक्ष अपील दायर की। अपील, जो 2002 के क्रमांक 282 पर दर्ज की गई थी, 20 जनवरी 2003 को खारिज कर दी गई।वित्तीय आयुक्त-सह-सचिव द्वारा अपील को खारिज करते हुए पारित आदेश का ऑपरेटिव भाग इस प्रकार है: -

"फाइल पर उपलब्ध रिकार्ड के अध्ययन से पता चलता है कि इस दौरान जांच के दौरान अपीलकर्ता का बयान भी चार बार दर्ज किया गया।इसके बाद आक्षेपित आदेश पारित करने से पहले प्रतिवादी सं. 1 ने अपीलकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिस पर उसने स्वीकार किया कि उसने अपना लिखित उत्तर प्रतिवादी संख्या के साथ प्रस्तुत किया और उसके बाद प्रतिवादी सं. 1 ने आक्षेपित आदेश पारित करने से पहले अपीलकर्ता को व्यक्तिगत रूप से भी सुना, लेकिन अपीलकर्ता ने न तो कारण बताओ नोटिस का लिखित उत्तर दिया और न ही अपनी व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान प्रतिवादी सं. 1 ने इस आशय की आपत्ति उठाई कि अपीलकर्ता को साक्ष्य प्रस्तुत करने का प्रभावी अवसर नहीं दिया गया। अत: इस स्तर पर पहली बार यह आपत्ति निरर्थक है। इसके अलावा, रिकॉर्ड पर उपलब्ध अपीलकर्ता के बयान को चार बार दर्ज करने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि इस आशय का तर्क कि अपीलकर्ता को सबूत पेश करने के लिए कोई प्रभावी अवसर नहीं दिया गया था, भौतिक तथ्य को दबाने के समान है। इसलिए, यह अपील केवल इस आधार पर खारिज करने योग्य है, जिसे पूर्ण पीठ प्राधिकरण 1978 पीएलजे 373 के रूप में उद्धृत किया गया है। विकास कार्यों की मूल्यांकन रिपोर्ट कार्यकारी अभियंता द्वारा तैयार की गई थी, जिसके आधार पर कार्यों का निरीक्षण करने के बाद आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। अन्य बातों के साथ-साथ स्वयं अपीलकर्ता की उपस्थिति में खेल। उक्त मूल्यांकन रिपोर्ट रिकॉर्ड पर उपलब्ध है और उक्त कार्यकारी अभियंता ने अपीलकर्ता के बयान को भी दर्ज किया है और कार्यकारी अभियंता द्वारा दर्ज किया गया उक्त बयान स्वयं अपीलकर्ता के हस्ताक्षर द्वारा संलग्न किया गया है। इसलिए, इस आशय के तर्क कि ग्राम पंचायत द्वारा किए गए कार्यों का कोई उचित मूल्यांकन

नहीं किया गया है और यहां तक कि मौके का निरीक्षण भी नहीं किया गया है, बिल्कुल रिकॉर्ड के खिलाफ हैं और भौतिक तथ्यों को दबाने के समान हैं। इसलिए, पूर्ण पीठ प्राधिकरण द्वारा 1978 पीएलजे 373 के रूप में उद्धृत यह अपील इसी आधार पर खारिज करने योग्य है। आक्षेपित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि इसमें अपीलकर्ता द्वारा उसकी व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान प्रतिवादी संख्या द्वारा लिए गए बचाव की सामग्री शामिल है। 1 और अपीलकर्ता के कारण बताओ नोटिस के जवाब की सामग्री और लागू आदेश में अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत उक्त उत्तर से सहमत नहीं होने के कारण भी शामिल हैं। इसलिए, इस आशय का तर्क कि अपीलकर्ता द्वारा उसके उत्तर में उठाए गए बिंदुओं पर न तो विचार किया गया और न ही आक्षेपित आदेश में चर्चा की गई, किसी भी योग्यता से रहित है। इसके अलावा, सिविल अपील संख्या में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 5 अप्रैल, 2002 के फैसले के तहत। 2002 का 2477, अंतरिम आदेश पारित करते समय प्रथम दृष्टया आरोपों पर विचार किया जाना है और विस्तृत कारण दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है अन्यथा यह लंबित जांच को प्रभावित कर सकता है। तत्काल संदर्भ के लिए उक्त निर्णय नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:-

> *अंतरिम आदेश पारित करते समय प्रथम दृष्टया आरोपों पर विचार किया जाना चाहिए और विस्तृत कारण दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है अन्यथा यह लंबित जांच को प्रभावित कर सकता है।आक्षेपित आदेश एक अंतरिम आदेश है क्योंकि अपीलकर्ता के खिलाफ पहले से ही लंबित नियमित जांच के समापन के बाद अंतिम आदेश पारित किया जाना बाकी है। इस प्रकार आक्षेपित आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पूर्वोक्त फैसले के बिल्कुल अनुरूप है। इस प्रकार किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह अपील खारिज करने योग्य है।"*

(4) इसके बाद सरपंच ने सी.डब्ल्यू.पी. दायर की। संख्या 3208/2003, क्रमशः उपायुक्त और वित्तीय आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 19 दिसंबर, 2002 और 20 जनवरी, 2003 के विरुद्ध। रिट याचिका एक डिवीजन बेंच के सामने आई और 27 फरवरी, 2003 को वापस ले ली गई मानकर खारिज कर दी गई।

(5) इस आदेश के पूर्ववर्ती पैरा में उल्लिखित विस्तृत तथ्य देने के बाद याचिकाकर्ता ने सी.डब्ल्यू.पी. क्रमांक 11144 सन् 2003 दायर की। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि श्री चंद राम, प्रतिवादी संख्या।

2, नियमित जांच की प्रक्रिया शुरू की और शिकायतकर्ता सहित कई गवाहों की जांच की, जिन्होंने सरपंच के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। पैरा नंबर 4 में यह भी आरोप लगाया गया कि सरपंच ने चंद राम को प्रभावित किया था और परिणामस्वरूप चंद राम याचिकाकर्ता और अन्य गवाहों को उचित अवसर देकर नियमित जांच नहीं कर रहे थे, जिन्हें सरपंच के खिलाफ आरोप साबित करना था। आरोप यह है कि याचिकाकर्ता ने गांव के अन्य निवासियों के साथ, जो सरपंच के कुकर्म से प्रभावित थे, प्रतिवादी नंबर 1, तत्कालीन उपायुक्त, कैथल से संपर्क किया था, जिन्होंने उन्हें झूठा आश्वासन भी दिया था। प्रतिवादी नंबर 2, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी श्रीचंद राम के खिलाफ उपायुक्त के समक्ष एक शिकायत दायर करने का भी दावा किया गया था। जांच अधिकारी चांद राम का स्थानांतरण कर किसी अन्य अधिकारी को जांच सौंपने का अनुरोध किया गया। पैरा 5 में, यह आरोप लगाया गया था कि सरपंच का बेटा INDL पार्टी की तत्कालीन सरकार में सक्रिय भागीदार था, जो श्री अनुराग अग्रवाल, उपायुक्त, प्रतिवादी संख्या 1, साथ ही श्री चंद राम पर दबाव डाल रहा था। प्रतिवादी संख्या 2, और वे सरपंच का पक्ष ले रहे थे। पैरा 6 में यह आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता के साथ-साथ गांव के अन्य निवासियों को नियमित जांच में नुकसान हो आशंका व्यक्त की गई थी कि प्रतिवादी नंबर 2 चांद राम के आचरण के कारण, सरपंच के खिलाफ आरोप साबित नहीं हो पाएंगे। ने की संभावना थी, जो कि प्रतिवादी संख्या 2 श्री चंद राम द्वारा की जा रही थी, क्योंकि गवाहों की जांच नहीं की जा रही थी और श्री चंद राम याचिकाकर्ता के साथ-साथ अन्य गवाहों को गंदी-गंदी गालियां दे रहा था और गवाहों पर सरपंच के पक्ष में बयान देने के लिए दबाव बना रहा था। आशंका व्यक्त की गई थी कि प्रतिवादी नंबर 2 चांद राम के आचरण के कारण, सरपंच के खिलाफ आरोप साबित नहीं हो पाएंगे। यह उल्लेख करना उचित होगा कि 2003 की संशोधित सिविल रिट याचिका संख्या 11144 में चंद राम, प्रतिवादी नंबर 2 को नाम देकर शामिल किया गया था, इसके अलावा चन्नो देवी, सरपंच, अमर सिंह, एम.एल.ए., बाघ सिंह, एम.एल.ए., याचिका में यह भी खुलासा किया गया था पैरा 10 में, सरपंच के हाथों पंचायत के धन का दुरुपयोग। यह आरोप लगाया गया था कि निलंबन आदेश के बावजूद, जिसे वित्तीय आयुक्त-सह-सचिव और इस न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था, उन्होंने रुपये की राशि निकाल ली थी। उन्होंने 7 लाख रुपये का गलत उपयोग किया और कोई विकास कार्य नहीं किया। आरोप है कि सरपंच ने रु.7 लाख रुपए की राशि निकालने के लिए प्रस्ताव पर एक पंच सदस्य का अंगूठा (एलटीआई) लगवा लिया यह दर्शाते हुए कि उस पंच सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन मिलनी है। आरोप है कि निलंबन के बाद सरपंच को 7 लाख रुपये की राशि निकालने का कोई अधिकार नहीं है। याचिका के साथ बैंक विवरण की प्रतियां संलग्न की गई थीं, जिन्हें अनुलग्नक पी-9 और पी-10 के रूप में चिह्नित किया गया था। बचत बैंक खाता संख्या 9610 (पी-10) के अवलोकन से पता चलता है कि 3 फरवरी 2003 को रु.10,000 + रु.10,000 = रु. 20,000, सेल्फ चेक नंबर 45 और 46 से 20,000 रुपये निकाले गए। 18 फरवरी, 2003 को रु. 70,000 रुपये निकाले जा चुके थे। जांच अधिकारी चंद राम पर अनुचित दबाव डालने के लिए संशोधित सिविल रिट याचिका में शामिल किए गए दो विधायकों अमर सिंह और बाघ सिंह के खिलाफ पैरा 15 में विशिष्ट आरोप लगाए गए थे। उन आरोपों को पढ़ना दिलचस्प है, जो इस प्रकार हैं:-

"15. याचिकाकर्ता के साथ-साथ अन्य शिकायतकर्ताओं को भी प्रतिवादी संख्या 4 पर कोई विश्वास नहीं है क्योंकि निष्पक्ष और उचित जांच नहीं की जाएगी, यदि वही पद चला जाएगा तो निष्पक्ष न्याय नहीं मिल पाएगा। याचिकाकर्ता के साथ-साथ गांव के अन्य निवासी भी। इस प्रकार, याचिकाकर्ता ने समर्थन के लिए प्रतिवादी नंबर 1 से भी संपर्क किया ताकि निष्पक्ष और उचित जांच की जा सके, प्रतिवादी नंबर 1 ने भी निष्पक्ष और उचित जांच में अपनी असमर्थता दिखाई है क्योंकि प्रतिवादी नंबर 1 का बेटा प्रतिवादी नंबर 5 हलका एम.एल.ए. श्री अमर सिंह और श्री बाघ सिंह, एम.एल.ए. उचाना विधानसभा क्षेत्र, के बहुत करीब है। इस प्रकार, अमर सिंह और बाघ सिंह जो प्रतिवादी संख्या 6 और 7 हैं, याचिकाकर्ता के साथ-साथ आधिकारिक उत्तरदाताओं पर राजनीतिक दबाव डाल रहे हैं ताकि आधिकारिक उत्तरदाता प्रतिवादी संख्या 5 का समर्थन कर सकें। इस प्रकार, प्रतिवादी संख्या 5 इस हद तक दुस्साहस कर रहा है कि कार्यवाहक सरपंच को कार्यभार सौंपने के संबंध में इतने पत्र देने के बाद भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उसी के संदर्भ में वह दबाव डाल रही है। ताकि निष्पक्ष और उचित जांच न हो सके।"

(6) आरोप यह भी लगाए गए कि निलंबित सरपंच गांव में पंचायत और विकास कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए किसी अन्य को कार्यभार नहीं सौंप रहा है। जाहिर है, सरपंच का अवज्ञाकारी आचरण आई.एन.डी.एल. के आज की सरकार के स्थानीय विधायकों के प्रभाव के कारण था।

(7) रिट याचिका 21 जुलाई, 2003 को दायर की गई थी जब याचिका में संशोधन के लिए प्रार्थना की गई थी। इसके बाद 4 अगस्त, 2003 को संशोधित याचिका दायर की गई, जो 5 अगस्त, 2003 को सुनवाई के लिए आई। उसी दिन वरिष्ठ उप महाधिवक्ता, हरियाणा, श्री रणधीर सिंह ने निर्देश मांगने के बाद खंडपीठ के समक्ष एक बयान दिया और उसे इस प्रकार लिखा गया:-

"निर्देशों के बाद हरियाणा के विद्वान वरिष्ठ उप महाधिवक्ता श्री रणधीर सिंह ने हमें सूचित किया कि रिट याचिका में व्यक्त याचिकाकर्ता की आशंकाएं पूरी तरह से निराधार हैं और जांच को शीघ्रता से समाप्त करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे, किसी भी हस्तक्षेप से या प्रारंभिक निष्कर्षों के संबंध में याचिकाकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्रियों से अप्रभावित होते हुए।

याचिकाकर्ता को प्रारंभिक जांच के दौरान दर्ज किए गए निष्कर्षों के संबंध में जो भी साक्ष्य उचित लगे उसे प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दी गई है।

विचारित जांच रिपोर्ट की एक प्रति केवल रिकॉर्ड के लिए इस न्यायालय के रजिस्ट्रार (जनरल) के समक्ष एक हलफनामे के माध्यम से रिकॉर्ड पर लाने का निर्देश दिया जाता है।

तदनुसार रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

इस आदेश की एक प्रति श्री रणधीर सिंह, विद्वान वरिष्ठ उप महाधिवक्ता, हरियाणा को कल तक आगे के प्रसारण और संबंधित अधिकारियों द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई के लिए सौंप दी जाए।

एसडी-/.....
(बिनोद कुमार रॉय),
मुख्य न्यायाधीश।
एसडी/-.....
(जस्टिस जे.एस. नारंग)
न्यायाधीश
05 अगस्त 2003"

(8) 22 अक्टूबर, 2003 को याचिकाकर्ता ने तत्काल अवमानना याचिका दायर की, जिसमें आरोप लगाया गया कि 5 अगस्त, 2003 को याचिका खारिज होने के बाद, वास्तव में कुछ भी नहीं किया गया था और सरपंच को 4 अगस्त, 2003 के आदेश के तहत पहले ही बहाल कर दिया गया था और समर्थन भी किया जा चुका है जिसका पृष्ठांकन 7 अगस्त 2003 को किया जाना दर्शाया गया है। उपर्युक्त आदेश स्पष्ट रूप से खंडपीठ के समक्ष दिए गए वचन के खिलाफ था जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी हस्तक्षेप से प्रभावित हुए बिना और याचिकाकर्ता या याचिकाकर्ता या किसी और के द्वारा रिकॉर्ड पर लाई जाने वाली सामग्री के आधार पर जांच शीघ्रता से पूरी की जानी थी। याचिकाकर्ता को अन्य लोगों के साथ-साथ उचित समझे जाने वाले साक्ष्य प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दी गई।

(9) जवाब में, प्रतिवादी नंबर 1 श्री अनुराग अग्रवाल, उपायुक्त, कैथल ने कहा था कि खंडपीठ के आदेशों का अनुपालन किया गया और कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद 4 अगस्त, 2003 को सरपंच को बहाल कर दिया गया। जांच रिपोर्ट की एक प्रति अनुलग्नक आर-1 के रूप में रिकॉर्ड पर रखी गई है। प्रारंभिक आपत्तियों के पैरा 2 में, श्री अग्रवाल ने शपथ पत्र पर निम्नलिखित बयान दिया था: -

"2. यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि सी.डब्ल्यू.पी. 11144/2003 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 5 अगस्त, 2003 को पारित आदेश महाधिवक्ता, हरियाणा, चंडीगढ़ को पत्र संख्या 31767, दिनांक 7 अगस्त, 2003 के माध्यम से सूचित किया था और प्रतिवादी संख्या 1 के कार्यालय में दिनांक 11 अगस्त, 2003 को प्राप्त हुआ था, जबकि बहाली के आदेश सरनांच. ग्राम पंचायत फ़िरोज़नूर

को 4 अगस्त, 2003 कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पारित किया गया था। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय के 5 अगस्त, 2003 के आदेश में दिए गए निर्देशों के अनुसार, प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा की गई जांच रिपोर्ट की प्रति रजिस्ट्रार (जनरल) पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, पंजीकृत पत्र संख्या 5477-78, दिनांक 9 सितंबर, 2003, को एक हलफनामे के माध्यम से प्रस्तुत की गई है। अतः प्रतिवादियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। उक्त पत्र की एक प्रति अनुलग्नक आर-एल के रूप में संलग्न है" (जोर दिया)"

(10) उत्तर के पैरा 1 में यह स्वीकार किया गया कि डिवीजन बेंच द्वारा पारित 5 अगस्त, 2003 के आदेशों का अनुपालन 25 जुलाई, 2003 को पहले ही किया जा चुका था जब चंद राम, प्रतिवादी नंबर 2 ने जांच पूरी की और अंतिम आदेश प्रतिवादी क्रमांक 1 श्री अग्रवाल 4 अगस्त 2003 को पारित किए गए। यह भी कहा गया है कि जांच रिपोर्ट की एक प्रति इस न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को पंजीकृत पत्र दिनांक 9 सितंबर, 2003 (आर-एल) के माध्यम से भेजी गई थी। पैरा 4 में दावा किया गया है कि 25 जुलाई 2003 को प्रतिवादी नंबर 2 चंद राम द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद 28 जुलाई 2003 को सरपंच को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए सरपंच को 4 अगस्त 2003 को बुलाया गया था। सुनवाई के बाद 4 अगस्त 2003 को सरपंच को इस निर्देश के साथ बहाल कर दिया गया कि धारा 53(2) हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए कैश-इन-हैंड के रूप में रखी गई राशि पर 21% की दर से दंडात्मक ब्याज सरपंच से वसूला जाए। सरपंच द्वारा गबन किए गए रुपये की राशि रु.98395 रुपए तत्काल ग्राम पंचायत के खाते में जमा कराए जाने थे। दावा किया गया है कि सरपंच ने रुपये की राशि जमा कर दी है. 4 अगस्त 2003 को ही ग्राम पंचायत के बैंक खाते में रु.98,395 ये भौतिक कथन हैं, जिन्हें अन्य पैराग्राफों में भी कमोबेश दोहराया गया है। इस न्यायालय द्वारा 5 अगस्त, 2003 को पारित आदेश के आलोक में सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 11144/2003, 19 अगस्त 2005 को श्री अग्रवाल द्वारा एक और हलफनामा दायर किया गया था, जिसमें कहा गया था कि जिला अटॉर्नी, कैथल से कुछ कानूनी राय प्राप्त की गई थी। जिला अटॉर्नी की राय थी कि आगे कोई कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जांच रिपोर्ट 9 सितंबर, 2003 को इस न्यायालय के रजिस्ट्रार को पहले ही सौंप दी गई थी। सी.डब्लू.पी. क्रमांक 11144/2003 के संबंध में, पैरा 5 में दावा किया गया है कि 5 अगस्त, 2003 को महाधिवक्ता के कार्यालय या किसी अन्य क्वार्टर से श्री अग्रवाल को कोई संचार प्राप्त नहीं हुआ था। दावा है कि हरियाणा के वरिष्ठ उप महाधिवक्ता को गलत जानकारी देने वाले किसी भी अधिकारी की पहचान कर उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी। प्रतिवादी नंबर 2 चंद राम द्वारा दायर जवाब लगभग श्री अग्रवाल के समान है, पूछताछ में याचिकाकर्ता और अन्य को दिए गए अवसर के संबंध में कुछ विवरणों को छोड़कर।

(11) 5 अगस्त, 2005 को, जब मामला इस न्यायालय के समक्ष आया, तो पक्षों के विद्वान वकीलों को सुनने के बाद प्रथम दृष्टया विचार व्यक्त किया गया कि उत्तरदाताओं द्वारा घोर अवमानना की गई थी। 5 अगस्त, 2005 के आदेश में व्यक्त इस न्यायालय का दृष्टिकोण इस प्रकार है:-

"पक्षों के विद्वान वकीलों को काफी विस्तार से सुनने के बाद, मेरा मानना है कि 5 अगस्त, 2003 को इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की घोर अवमानना हुई है। इस न्यायालय की एक खंडपीठ के समक्ष यह कहा गया था कि रिट याचिका में व्यक्त याचिकाकर्ता की आशंका पूरी तरह से निराधार थी और उत्तरदाताओं द्वारा किसी भी हस्तक्षेप से प्रभावित हुए बिना और प्रारंभिक निष्कर्षों के संबंध में याचिकाकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा रिकॉर्ड लाए गए सामग्रियों के बिना, सख्ती से मामले को शीघ्रता से समाप्त करने के लिए सभी प्रयास किए जाने थे। माननीय खंडपीठ द्वारा आगे यह देखा गया कि याचिकाकर्ता को प्रारंभिक जांच के दौरान दर्ज किए गए निष्कर्षों के संबंध में जो भी साक्ष्य उचित लगे उसे प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दी गई थी। यह रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि 5 अगस्त, 2003 के बाद कुछ भी नहीं किया गया है और वास्तव में सरपंच को बहाल करने का आदेश 4 अगस्त, 2003 को पारित किया गया है। खंडपीठ के समक्ष दिए गए बयान और प्रतिवादी क्रमांक 1 के शपथ पत्र के पैरा क्रमांक 3 में उसके द्वारा उठाए गए रुख की तुलना करने पर कई सवाल उठेंगे। । शपथ पत्र में कहा गया है कि 4 अगस्त 2003 को जांच के आधार पर सरपंच को बहाल किया गया है। यदि ऐसा था, तो उत्तरदाताओं के पास खंडपीठ के समक्ष यह बयान देने का कोई अवसर नहीं था कि जांच किसी भी हस्तक्षेप से अप्रभावित रहेगी और याचिकाकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री पर सख्ती से आधारित होगी। इसके अलावा, उत्तरदाताओं के पास खंडपीठ के समक्ष यह कहने का कोई अवसर नहीं था कि याचिकाकर्ता को उस संबंध में जो भी साक्ष्य उचित लगे उसे जांच अधिकारी के समक्ष पेश करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए।

उपर्युक्त स्थिति प्रथम दृष्टया सुलह से कोई समाधान नहीं निकालती है क्योंकि यदि 4 अगस्त, 2003 को सरपंच को बहाल करने का आदेश पारित किया गया था, तो विद्वान राज्य वकील के लिए डिवीजन बेंच के समक्ष ऐसा बयान देना आवश्यक था, जो उत्तरदाताओं से निर्देश प्राप्त करने के बाद में दिया गया था। इसलिए, प्रथम दृष्टया मेरा मानना है कि उत्तरदाता अवमानना के दोषी हैं और उनका आचरण अपमानजनक है। इसके लिए कुछ सुधारात्मक पद्धति की आवश्यकता थी।"

(12) 5 अगस्त, 2005 के आदेश के पारित होने के बाद क्रमशः श्री अग्रवाल और श्री चंद राम, प्रतिवादी संख्या 1 और 2 द्वारा अतिरिक्त हलफनामा दायर किया गया था। हालाँकि, उन हलफनामों को दाखिल करने से कोई सुधार नहीं हुआ।

(13) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री मदन पाल ने तर्क दिया है कि वरिष्ठ उप महाधिवक्ता, हरियाणा द्वारा दिया गया एक अंडरटेकिंग निश्चित रूप से भ्रामक है और झूठा साबित हुआ है। विद्वान वकील के अनुसार उत्तरदाताओं द्वारा उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति का खंडन नहीं किया गया है। उन्होंने कहा है कि ऐसी स्थिति में क्रमशः 'सिविल अवमानना' और 'आपराधिक अवमानना' को परिभाषित करने वाली अधिनियम की धारा 2 (बी) और धारा 2 (सी) की आवश्यकता पूरी हो गई है। अपने प्रस्तुतीकरण के समर्थन में विद्वान वकील ने **मोहम्मद असलम उर्फ भूरे बनाम भारत संघ (1)** मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा जताया है, जो अयोध्या में 'राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद' की संरचना के विध्वंस से संबंधित है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मुख्यमंत्री द्वारा व्यक्तिगत रूप से और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दिए गए वचन के आधार पर, वचन पत्र के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किए गए थे, जिनकी जानबूझकर अवज्ञा किया गया था। विद्वान वकील ने सुप्रीम कोर्ट के एक अन्य फैसले पर भी भरोसा जताया है **डेविड जज बनाम हन्ना ग्रेस जूड (2)** के मामले में, जहां फिर से आदेश के आधार पर न्यायालय को दिए गए वचन का उल्लंघन किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने दोषी ठहराया था अवमानना करनेवाला। उन्होंने **लक्ष्मी नारायण बनाम आर.एन. प्रशर और अन्य (3)**, मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा जताया है।

(14) हरियाणा के विद्वान महाधिवक्ता श्री हवा सिंह हुडा, प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित हुए और तर्क दिया कि श्री अग्रवाल द्वारा सरपंच को बहाल करने के 4 अगस्त, 2003 के आदेश को याचिकाकर्ता द्वारा अपील में चुनौती दी गई थी। आदेशों को बरकरार रखा गया है और इसलिए, याचिकाकर्ता 5 अगस्त, 2003 को खंडपीठ के समक्ष दिए गए वचन के संबंध में शिकायत करने का हकदार नहीं है। वित्तीय आयुक्त और सचिव के समक्ष याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील की एक प्रति, 2003 की अपील संख्या 209 होने के कारण, अनुबंध आर -4 के रूप में रिकॉर्ड पर रखी गई है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि श्री अग्रवाल, जो अब गुड़गांव में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के प्रशासक के रूप में तैनात हैं, ने पहले ही कैथल के वर्तमान उपायुक्त से जांच शुरू करने और उस व्यक्ति की पहचान करने का अनुरोध किया है, जिसने 5 अगस्त, 2003 को उत्तरदाताओं की ओर से बयान देने के लिए वरिष्ठ उप महाधिवक्ता को निर्देश दिया होगा। महाधिवक्ता के अनुसार ऐसी स्थिति में प्रतिवादियों पर कोई इरादा नहीं लगाया जा सकता है, खासकर जब रिकॉर्ड से पता चलता है कि सरपंच ने रुपये की राशि जमा की थी। 4 अगस्त, 2003 को 98,395 और जांच 25 जुलाई, 2003 को पूरी हुई।

(15) न्यायालय द्वारा बार-बार पूछे जाने पर, विद्वान महाधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के बयान के आधार पर रिट याचिका को खारिज करने से न्याय प्रशासन में उत्पन्न बाधा को दूर करने के

लिए कोई उपाय नहीं बता सके। वरिष्ठ उप महाधिवक्ता, हरियाणा के माध्यम से। विद्वान महाधिवक्ता को बार-बार इस प्रश्न का सामना करना पड़ा कि रिट याचिका का क्या होगा, जिसे वरिष्ठ उप महाधिवक्ता के माध्यम से प्रतिवादी नंबर 1 और 2 द्वारा दिए गए बयान के आधार पर खारिज कर दिया गया था। हालाँकि, वह इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं दे सके, सिवाय यह बताने के कि 25 जुलाई, 2003 या 4 अगस्त, 2003 को पारित आदेश और बाद में अधिकारियों द्वारा बरकरार रखे गए आदेशों को याचिकाकर्ता द्वारा एक और याचिका दायर करके फिर से चुनौती दी जा सकती है।

(16) पक्षों के विद्वान वकील को सुनने और गहन विचार करने के बाद, मेरा विचार है कि यह मामला न्याय प्रशासन में बाधा डालने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। संशोधित रिट याचिका 4 अगस्त, 2003 को दायर की गई थी, जो 5 अगस्त, 2003 को विचार के लिए आई। मामले की तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए, डिवीजन बेंच ने महाधिवक्ता को नोटिस जारी किया था। जब मामला उठाया गया, तो यह बयान देकर याचिका खारिज कर दी गई कि याचिकाकर्ता को जांच में पूरा मौका दिया जाना था और उसकी दुर्भावनापूर्ण और पक्षपातपूर्ण सभी आशंकाएं निराधार थीं। तदनुसार, याचिकाकर्ता को प्रारंभिक जांच के दौरान दर्ज किए गए निष्कर्षों के संबंध में जो भी साक्ष्य उचित लगे, जो स्पष्ट रूप से सरपंच के खिलाफ थे, पेश करने की छूट देते हुए रिट याचिका का निपटारा कर दिया गया।हालाँकि, यह माना गया है कि डिवीजन बेंच द्वारा 5 अगस्त, 2003 के आदेश में दर्ज बयान देने से पहले, सरपंच की बहाली का आदेश पहले ही पारित किया जा चुका था और उसने रुपये की राशि जमा कर दी थी। 4 अगस्त, 2003 को दंडात्मक ब्याज सहित 98,395 रु. आगे यह भी माना गया कि जांच 25 जुलाई 2003 को पूरी हो गई थी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 25 जुलाई, 2003 को जांच पूरी होने और 4 अगस्त, 2003 को सरपंच की बहाली के आदेश पारित होने के बावजूद, श्री अग्रवाल और श्री चंद राम, प्रतिवादी संख्या 1 और 2 वरिष्ठ उप के माध्यम से न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए हैं। महाधिवक्ता श्री रणधीर सिंह ने 5 अगस्त, 2003 को एक बयान दिया, जो रिकॉर्ड से बाहर नहीं है। इस तथ्य के अलावा कि 5 अगस्त, 2003 को न्यायालय को दिए गए वचन का घोर उल्लंघन किया गया है और यह अधिनियम की धारा 2 (बी) के अर्थ में नागरिक अवमानना का गठन करता है, प्रतिवादियों द्वारा दिया गया गलत बयान न्याय प्रशासन में बाधा डालने की सीमा पर है। . अधिनियम की धारा 2(बी) और 2(सी) इस प्रकार है:-

> ***"2. अवमानना की परिभाषा.***
>
> *न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 के 70 में धारा 2 में प्रावधान परिभाषित करता है:*
>
> ***(बी) 'सिविल अवमानना'** का अर्थ है किसी भी निर्णय, डिक्री, निर्देश, आदेश, रिट, या अन्य प्रक्रिया के प्रति जानबूझकर अवज्ञा करना, किसी अदालत को दिए गए वचन का जानबूझकर उल्लंघन करना;*

*(सी) **'आपराधिक अवमानना'** का अर्थ है किसी भी मामले का प्रकाशन (चाहे शब्दों द्वारा, बोले गए या लिखित या संकेतों द्वारा या दृश्य प्रतिनिधित्व या अन्यथा) या कोई अन्य कार्य करना, जो भी हो-*

(i) किसी न्यायालय को बदनाम करता है या बदनाम करने की प्रवृत्ति रखता है, या उसके अधिकार को कम करता है या कम करने की प्रवृत्ति रखता है; या

(ii) किसी भी न्यायिक कार्यवाही के उचित पाठ्यक्रम में पूर्वाग्रह, या हस्तक्षेप करता है या हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति रखता है; या

(iii) हस्तक्षेप करता है या हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति रखता है, या बाधा डालता है या बाधा डालने की प्रवृत्ति रखता है"

(17) उपर्युक्त प्रावधानों के अवलोकन से पता चलता है कि नागरिक अवमानना किसी न्यायालय को दिए गए वचन के जानबूझकर उल्लंघन से गठित होती है और आपराधिक अवमानना में कोई भी मामला या कोई अन्य कार्य करना शामिल होगा, जो अन्य बातों के अलावा, हस्तक्षेप करता है या हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति रखता है या न्याय प्रशासन में बाधा डालना या बाधा डालने की प्रवृत्ति रखना।

(18) यह स्पष्ट है कि आदेशों पर विचार करके समय को 5 अगस्त, 2003 तक वापस नहीं लाया जा सकता है, जो कि श्री अग्रवाल, प्रतिवादी नंबर 1 और श्री चंद राम प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा दिए गए बयान की अनुपस्थिति में डिवीजन बेंच द्वारा पारित किया जा सकता था। 2, वरिष्ठ उप महाधिवक्ता के माध्यम से। इसकी असंख्य संभावनाएँ हो सकती हैं और इस स्तर पर ऐसे आदेश की परिकल्पना या पूर्वानुमान करने का कोई भी प्रयास निरर्थक होगा। हालाँकि, एक बात बिना किसी संदेह के साबित हो गई है कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को एक बयान देकर निस्तारित कर दिया गया था, जो झूठा था।

(19) उत्तरदाताओं का यह रुख कि कोई बयान नहीं दिया गया, इस कारण से स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि अदालतें महाधिवक्ता या अदालत में किसी अन्य राज्य के वकील द्वारा दिए गए बयानों के पीछे नहीं जा सकती हैं। उन बयानों को प्रथम दृष्टया सही मानना होगा क्योंकि अगर उन बयानों पर संदेह किया गया तो न्याय की मशीनरी चरमरा जाएगी और विफल हो जाएगी। इसलिए, मुझे उत्तरदाताओं द्वारा अपनाए गए रुख में कोई सार नहीं दिखता।

(20) यह समान रूप से साबित हुआ है कि उत्तरदाता नंबर 1 श्री अनुराग अग्रवाल और प्रतिवादी नंबर 2 श्री चंद राम, जो उपायुक्त और खंड विकास और पंचायत अधिकारी, गुल्हा हैं, की ओर से बयान दिए गए थे। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि महाधिवक्ता या किसी अन्य श्रेणी के राज्य वकील द्वारा दिए गए बयान को सत्य माना जाना चाहिए क्योंकि किसी भी अन्य दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप विनाशकारी परिणाम होंगे। प्रतिदिन बड़ी संख्या में मामलों में विद्वान राज्य वकील बयान देते हैं, जिन्हें सत्य माना

जाता है। किसी भी अन्य विपरीत दृष्टिकोण का परिणाम यह होगा कि महाधिवक्ता या किसी राज्य वकील द्वारा दिया गया कोई भी बयान सत्य नहीं माना जाएगा, जिसे स्वीकार करना असंभव है। यह न्यायालय **हरदेव सिंह बनाम राजेश कुमार शर्मा के मामले में (4)** पाया है कि लिखित बयान में लिए गए गलत अग्रणी रुख के आधार पर, रिट याचिका खारिज कर दी गई थी और अवमानना न्यायालय के समक्ष भी वही रुख अपनाया गया था जब इस न्यायालय ने अवमाननाकर्ता को अवमानना का दोषी ठहराया था। उस मामले में हरदेव सिंह नामक व्यक्ति ने दावा किया था कि अनुभव प्रमाण पत्र को बर्खास्तगी के आदेश के रूप में माना जा रहा है। लिखित बयान में उपरोक्त दावे का खंडन करते हुए कहा गया कि हरदेव सिंह को कभी बर्खास्त नहीं किया गया था। लिखित बयान के साथ-साथ अदालत के समक्ष दिए गए मौखिक बयान के आधार पर रिट याचिका खारिज कर दी गई। उपरोक्त परिस्थितियों में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय लिया:

> "अब सवाल यह उठता है कि क्या प्रतिवादी की ओर से इस न्यायालय को गुमराह करने का यह प्रयास जिसके परिणामस्वरूप रिट याचिका खारिज हुई, नागरिक अवमानना है या नहीं। सिविल अवमानना का अर्थ न केवल न्यायालय के आदेश, निर्णय, डिक्री, निर्देश, रिट या अन्य प्रक्रिया की जानबूझकर अवज्ञा करना है, बल्कि न्यायालय को दिए गए वचन का जानबूझकर उल्लंघन भी है। मेरे विचार में, 19 नवंबर, 1981 का आदेश, वास्तव में, प्रतिवादी द्वारा दिए गए बयान पर इस न्यायालय द्वारा दिया गया एक निर्देश या आदेश था और इसी आधार पर रिट याचिका को निरर्थक मानकर खारिज कर दिया गया था। इसलिए, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी इस न्यायालय की सिविल अवमानना करने का दोषी है।"

(21) इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियाँ वर्तमान मामले के तथ्यों पर पूरी तरह से लागू होती हैं क्योंकि उस मामले में भी याचिका खारिज होने के बाद, प्रतिवादी ने दावा किया था कि याचिकाकर्ता ने खुद को ड्यूटी से अनुपस्थित कर लिया था और इसलिए, उसे सेवा में वापस नहीं लिया जा सकता था। , जबकि न्यायालय के समक्ष विपरीत रुख अपनाया गया था। वर्तमान मामले में भी, प्रतिवादियों द्वारा सरपंच के खिलाफ निष्पक्ष जांच कराने का आश्वासन देने वाले बयान पर रिट याचिका खारिज कर दी गई और रिट याचिका का निपटारा कर दिया गया। 5 अगस्त, 2005 के आदेश में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि उत्तरदाता अवमानना के दोषी थे और उनका आचरण अवमाननापूर्ण था। प्रतिवादियों द्वारा अवमानना को दूर करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। इसके विपरीत, दोनों प्रतिवादियों ने यह रुख अपनाकर एक रहस्यमय और अज्ञात अधिकारी पर जिम्मेदारी डालने की अपनी कार्रवाई को उचित ठहराने का प्रयास किया है कि उसने इस न्यायालय को गलत निर्देश दिए होंगे, जिसके कारण रिट का निपटान करना पड़ा। याचिका। ऐसा रहस्यमय व्यक्ति अस्तित्व में नहीं है। इसलिए, मैं दोनों उत्तरदाताओं को अधिनियम की धारा 2(बी) के तहत नागरिक अवमानना का दोषी घोषित करता हूं। दोनों प्रतिवादियों को 26 सितंबर,

2005 के लिए एक नोटिस जारी किया जाए, ताकि उन्हें सजा की अवधि पर सुनवाई का अवसर दिया जा सके।

<u>अस्वीकरण:</u>

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उदेश्यों के लिये निर्णय का अंग्रेज़ी सस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

सागर शर्मा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
नूँह, हरियाणा